



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2875]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 11, 2017/आश्विन 19, 1939

No. 2875]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2017/ASVINA 19, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2017

**का.आ 3290(अ).**—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन वाणिज्य विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है) देश भर में समुद्री उत्पाद उद्योग के सम्पूर्ण विकास के मुख्य उद्देश्य से 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास' (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) नामक केंद्रीय क्षेत्र की एक स्कीम के अधीन 'समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण' को सहायता अनुदान और सहायिकियाँ प्रदान करता है;

और स्कीम के अधीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) को दी जाने वाली सहायता अनुदान का उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ स्कीम के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार स्कीम के विभिन्न उप घटकों के अधीन मछुआरों, जलकृषि कृषकों, कामगारों, प्रौद्योगिकीविदों और व्यष्टिक निर्यातकों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राही कहा गया है) को प्रशिक्षण, फायदे प्रदान करने तथा जागरूकता कार्यक्रमों (जिसे इसमें इसके पश्चात एक साथ फायदाग्राही कहा गया है) के लिए किया जाता है:-

और, पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत व्यय अंतर्बलित है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिधान अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है; अर्थातः

1. (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक से यह अपेक्षित है कि वे आधार के कब्जे में होने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें।

(2) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं कराया है उससे अपेक्षित है कि वह 31 दिसंबर 2017 तक, आधार नामांकन कराने हेतु आवेदन करें, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने हेतु हकदार हो, उसे ऐसे व्यक्ति आधार हेतु नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र [भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) पर सूची उपलब्ध है, वेबसाइट [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)] पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग से यह अपेक्षित है कि वह अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से ऐसे फायदाग्राहियों के बिना जिन्होंने अभी तक आधार नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन कराने की सुविधाओं की प्रस्थापना करे और उस दशा में जहां संबंधित ब्लॉक या तालुका अथवा तहसील में आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है वहां विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या रजिस्ट्रार स्वयं यूआईडीएआई बनकर सुविधाजनक अवस्थानों में आधार नामांकन सुविधाएं, उपलब्ध कराएंगी:

परन्तु ऐसे व्यक्ति को आधार समनुदेशित किए जाने तक इस स्कीम के अधीन निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए फायदा दिए जाएंगे अर्थातः

(क) (i) यदि उसने आधार के लिए नामांकन कराया है तो उसके आधार नामांकन की आई डी स्लिप; अथवा

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (2) में यथा विहित और आधार नामांकन कराने के लिए गए अनुरोध की एक प्रति

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक:

(i) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र या

(ii) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालान अनुज्ञप्ति

(iii) उस व्यक्ति की फोटो सहित पहचान प्रमाण पत्र जिसे राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा आधिकारिक पत्रशीर्ष पर जारी किया गया हो; या

(iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(v) पासपोर्ट; या

(vi) राशनकार्ड; या

(vii) फोटो सहित बैंक पासबुक अथवा पोस्ट ऑफिस पासबुक; या

(viii) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

परन्तु यह भी कि उपर्युक्त दस्तावेज विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा जांचे जाएंगे:

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध फायदे प्रदान करने के लिए, विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं अर्थातः-

(1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आधार की आवश्यकता के बारे में फायदाग्राहियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा और व्यक्तिगत सूचना दी जाएगी तथा यदि उन्होंने पहले से अपना नामांकन नहीं कराया है तो 31 दिसंबर, 2017 तक अपने क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केंद्र पर अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) यदि आस – पास के क्षेत्रों जैसे ब्लॉक या तालुका या तहसील में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन न करा पाए हों तो विभाग अपने कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा और फायदेग्राही अपना नाम, पता, मोबाइल नं. और पैरा 1 के उप पैरा (3) के प्रथम परन्तुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य विवरण देकर आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध कार्यान्वयन एजेंसी के अभिहित अधिकारियों के पास या इस प्रयोजन के लिए दिए गए वेबपोर्टल के माध्यम से रजिस्टर कराएगा।

(3) यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू – कश्मीर राज्यों के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उस तारीख से प्रवृत्त होगी जिस तारीख को यह राजपत्र में प्रकाशित होगी।

[फा.सं. 11/3/2016- ईपी (एमपी)]

संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(MARINE PRODUCTS EXPORT DEVELOPMENT AUTHORITY)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2017

**S.O. 3290(E).**—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Commerce (*hereinafter referred to as the Department*) under the Ministry of Commerce and Industry in the Government of India is providing Grants-in-Aid and subsidies to the Marine Products Export Development Authority under the Central Sector Scheme of "Marine Products Export Development" (*hereinafter referred to as the Scheme*) with the key objective of overall development of the marine products industry across the country;

And whereas, the Grants-in-Aid given to the Marine Products Export Development Authority (*hereinafter referred to as the Implementing Agency*) under the Scheme, *inter-alia*, is used for giving trainings, subsidies and awareness programs (*hereinafter referred to as the benefits*) to the Fishers, Aquaculture farmers, Workers, Technologists and the individual exporters (*hereinafter together referred to as the beneficiaries*) under various sub-components of the Scheme as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government notifies the following, namely:

1. (1) An individual desirous of receiving the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual desirous of receiving the benefits under the Scheme who does not possess the Aadhaar number or, who has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make an application for Aadhaar enrolment by 31<sup>st</sup> December, 2017 in case he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, and such individuals may visit any Aadhaar Enrolment Centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) [www.uidai.gov.in](http://www.uidai.gov.in)) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

- (a) (i) If he or she has enrolled for Aadhaar, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) A copy of the request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2; and
- (b) any one of the following documents:
  - (i) Voter Identity Card issued by the Election Commission of India; or
  - (ii) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
  - (iii) Certificate of identity having photo of such individual issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an Official Letter Head; or
  - (iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or
  - (v) Passport; or
  - (vi) Ration Card; or
  - (vii) Bank Passbook or Post Office Passbook with photo; or
  - (viii) any other document specified by the Department:

Provided that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by the Department through its Implementing Agency for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the scheme, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements including the following, namely:-

- (1) wide publicity through media and individual notices shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to receive the benefits under the Scheme and, in case they are not enrolled, they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar Enrolment Centre available in their areas by 31<sup>st</sup> December, 2017 and the list of locally available enrolment centres shall be made available to them.
- (2) In case, the beneficiaries are not able to enrol due to non-availability of the enrolment centres within their vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and beneficiaries may register their requests for enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the first proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the designated officials of the Implementing Agency or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territory Administrations except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 11/3/2016-EP (MP)]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Jt. Secy.